विश्व की अद्भुत वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स में से एक हैं बुरकीना फासो के प्राचीन फैरस मैटलर्जी अवशेष। अफ्रीका के इस क्षेत्र में धातु का काम बेहद आम है तथा ईसापूर्व सन् 800 से हो रहा है। लौह उत्पादन बुरकीना फासो की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग था। आश्चर्य यह है कि इन लोगों ने 2800 साल पहले मैटलवर्क के लिए आवश्यक औजार व भवन बना लिए थे। आयरन मैटलवर्क के लिए मुख्यतया लोहे का खनन तो होता ही था, साथ ही, कभी-कभी सोना और मार्बल भी मिल जाता था, जिसका उपयोग ये लोग आभूषण और हथियार आदि बनाने के लिए करते थे। बुरकीना फासो की मैटलर्जी साइट्स पर बनी खूबसूरत वस्तुओं को अफ्रीका के आसपास के भागों में बेहद कीमती माना जाता था, क्योंकि अन्य स्थानों पर ना तो कच्चा माल उपलब्ध था ना ही उसके संवर्धन की टैक्नॉलजी थी। बुरकीना फासो के पांच शहरों में पांच मैटलवर्किंग कॉम्पलैक्स थे। पन्द्रह स्थानों पर इनके जो अवशेष मिले हैं उनमें प्राकृतिक नैचुरल ड्राफ्ट फरनैक्स (भट्टियाँ) हैं, जो लौह उत्पाद के लिए आवश्यक होते हैं। इन प्राकृतिक ड्राफ्ट फरनैस का उपयोग कच्चा लोहा पिघलाने के लिए और फिर लौह अयस्क से अशुद्धियाँ हटाने के लिए होता था। सबसे पुरानी भट्टी दौरौला में मिली है, जो संभवतया 800 ईसापूर्व की है। माना जाता है कि, सबसे पहले लोहा निकालने की शुरुआत यहीं हुई थी। एक अन्य शहर, बैंक्वे में जो फरनैस मिले हैं, वे 500 ईसापूर्व के हैं। इनमें से अधिकांश आंशिक रुप से भूमिगत हैं। अन्य तीन जगहों पर भी फरनैस मिले हैं पर ये दसवीं सदी ईस्वी और उसके बाद के हैं। बड़े फरनैस पांच शहरों में ही हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में छोटे-छोटे फरनैस हैं। इसका अर्थ है कि लौह अयस्क को पिघलाना, साफ करना, प्राचीन बुरकीना फासो की जीवन शैली और परम्परा का अंग था, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित किया गया। आज भी मैटलर्जी बुरकीना फासो की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। यहां की प्राचीन फैरस मैटलर्जी साइट्स को वर्ष 2019 में युनैस्को ने वर्ल्ड हैरिटेज साइट घोषित किया था।

सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया हाई कोर्ट ने

ई-मेल पर हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद नए मेयर के चुनाव की मतगणना रोक दी गई

- **हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सौम्या के वकील एम.एस. सहारण ने दोपहर एक बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर को ई-मेल भेजकर जानकारी दी।**
- **गुरुवार को भाजपा की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंहानिया में से किसी एक को चुनने के लिए पार्षदों ने वोटिंग की थी, पहली पेटी खुल चुकी थी पर कोर्ट का आदेश मिलने पर मतपेटियां सील कर दी गईं।**
- **ग्रेटर निगम के पूर्व आयुक्त, यज्ञमित्र सिंह के साथ हुए विवाद की न्यायिक जांच में दोषी मानते हुए राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को 27 सितंबर को बर्खास्त कर दिया था। साथ ही 6 साल तक निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था।**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 10 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के राज्य सरकार के आदेश को गुरूवार दोपहर निरस्त (रद्द) कर दिया। उधर ग्रेटर निगम मुख्यालय में महापौर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी थी और मतगणना भी शुरू हो गई थी। हाईकोर्ट का लिखित आदेश आने से पहले ही रिज़ल्ट आने की संभावना थी। इसी दौरान सौम्या के वकील एम.एस. सहारण ने दोपहर 1 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर को ई-मेल करके हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया रोकने का आग्रह किया। जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटों की काउंटिग रोककर मतपेटियां सील करा दीं। अब माना जा रहा है कि सौम्या गुर्जर शुक्रवार को वापस मेयर का पदभार संभाल सकती है।

दरअसल गुरूवार को ग्रेटर निगम में महापौर उपचुनाव था। भाजपा प्रत्याशी रश्मि सैनी और कांग्रेस उम्मीदवार हेमा सिंघानियां में से मेयर चुनने के लिए दोनों दलों के पार्षद वोट डाल चुके थे। दोपहर करीब 12 बजे मतगणना भी शुरू हो गई थी। पहली पेटी खुलने पर 38 वोट भाजपा और 33 वोट कांग्रेस को मिले थे। एक वोट निरस्त हो गया था। करीब आधे घंटे बाद मेयर के चुनाव का फैसला आने वाला था। तभी एक ई-मेल आया और काउंटिग रोक दी गई। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका था, जब एक ई-मेल के कारण काउंटिग रोककर मतपेटियां फिर से सील कर दी गई।

ज्ञात रहे कि राज्य सरकार ने गत 27 सितंबर को जयपुर ग्रेटर नगर निगम की तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर को सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। दरअसल ग्रेटर निगम के पूर्व आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद में राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को दोषी मानते हुए उन्हें महापौर पद से बर्खास्त कर दिया था। साथ ही 6 साल के लिए निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किये थे।

सौम्या की बर्खास्तगी के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर शील धाभाई को कार्यवाहक महापौर बनाया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पिछले दिनों चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके चलते भाजपा ने रश्मि सैनी को और कांग्रेस ने हेमा सिंघानियां को मेयर उम्मीदवार बनाया। करीब एक हफ्ते की बाड़ेबंदी के बाद गुरूवार को मतदान हुआ। हेमा का दावा था कि उनके साथ कांग्रेस के 49 और 5 निर्दलीय पार्षद है। भाजपा से असंतुष्ट पार्षद भी उनके साथ है। जबकि, रश्मि अपनी पार्टी के 85 पार्षद एकजुट होने के दावे के साथ जीत तय मान रही थी। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने क्रॉस वोटिंग की संभावना को देखते हुए अपने-अपने प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में कैद कर रखा था।

उधर गुरूवार को दोपहर ग्रेटर निगम के मेयर के चुनाव में सभी 146 पार्षद वोटिंग कर चुके थे। काउंटिग चल रही थी, लेकिन रिज़ल्ट से ठीक पहले चुनाव प्रक्रिया रोकी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अदालती आदेश से हालात ऐसे पैदा हो गए कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव प्रक्रिया रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ हुई न्यायिक जांच में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए सरकार से आधे घंटे में नया आदेश मांगा था। हालांकि सरकारी वकील ने हाईकोर्ट के सामने कोई नया आदेश पेश नहीं किया। इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि सौम्या गुर्जर को सुनवाई का पूरा मौका मिले।

माना जा रहा है कि सरकार के अगले एक्शन तक सौम्या मेयर रह सकती हैं। सरकार अब नोटिस देकर सौम्या का पक्ष सुनने के बाद सस्पेंड कर सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में अभी के हालात में सौम्या गुर्जर पुनः मेयर का पद संभाल सकती हैं।

अमेरिका हर माह एक लाख भारतीयों को वीज़ा देगा

- **इस घोषणा के बाद, चीन को पीछे छोड़कर भारत सबसे ज्यादा अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन जायेगा।**

नई दिल्ली, 10 नवंबर (वार्ता)। कोविड महामारी के बाद तेजी से सामान्य हो रही परिस्थितियों के बाद अमेरिका ने भारत के लिए वीज़ा आवेदनों को तेज़ी से निपटाने के लिए विशेष इंतजाम किये हैं और आशा जतायी है कि अगले वर्ष गर्मियों तक भारत चीन को पछाड़ कर दूसरा सर्वाधिक अमेरिकी वीज़ा पाने वाला देश बन जाएगा। इस बीच खुशी की बात यह है कि, अमेरिका ने घोषणा की है कि, हर महीने एक लाख भारतीयों को अमेरिकी वीसा जारी किये जायेंगे।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यहां कहा कि अमेरिका की सरकार के लिए भारत नंबर एक प्राथमिकता वाला देश है। हम नवंबर मध्य में वीज़ा स्लॉट खोलने जा रहे हैं और अगले वर्ष 2023 में अमेरिकी मिशन अधिक वीज़ा आवेदनों का न्यूनतम संभव समय में निस्तारण कर रहा होगा। इसके लिए हम स्थायी एवं अस्थायी काउंसलरों की भर्ती करेंगे और ड्रॉपबॉक्स केसों की संख्या भी बढ़ाएंगे।अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने कुशल एवं तकनीकी कामगारों के लिए एच श्रेणी और प्रबंधकीय वर्ग के लिए एल श्रेणी के वीज़ा के लिए एक लाख नये स्लॉट खोल दिये हैं। हमें आशा है कि भारत अगले वर्ष गर्मियों तक अमेरिकी वीसा पाने वाले देशों की श्रृंखला में चीन को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी वीज़ा हासिल करने के मामले में भारत, मैक्सिको के बाद नंबर दो देश हो जाएगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भारत को अगले वर्ष कोविड पूर्व की स्थिति की तुलना में कम से कम दस फीसदी अधिक वीज़ा जारी किये जाएंगे।

संजय राउत के तेवर नरम पड़ गये हैं?

- **संजय राउत ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उनको अपने मामले की पूरी सच्चाई बताऊंगा।**

मुंबई, 10 नवम्बर। पातरा चॉल स्कैम में 101 दिनों की जेल के बाद बेल पर बाहर निकले संजय राउत के तेवर अब क्या नरम पड़ गए हैं? उनके एक बयान से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। जेल से निकलने के बाद संजय राउत ने अब भाजपा से रिश्ते बदलने के संकेत दिए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करूंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं मोदी और शाह से मिलकर बताऊंगा कि क्या हुआ है और पूरा मामला क्या था। संजय राउत बुधवार शाम को ही जेल से बाहर आए हैं और सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने उनसे मुलाकात की।

ओ.बी.सी. आरक्षण मामले को लेकर हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रैफर होने पर काबीना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर निशाना साधा

- **खाचरियावास बोले, मेरा नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है।**

जयपुर, 10 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में ओबीसी वर्ग के पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण को ओबीसी कोटा में ही शामिल किया जाता है, जिसे लेकर विरोध चल रहा है। इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को उम्मीद थी कि वसुंधरा सरकार के समय लिए गए उक्त निर्णय को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को हुई कैबिनेट में बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले के स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेताओं में आपसी बयानबाजी शुरू हो गई है।

ओबीसी आरक्षण को लेकर विधायक हरीश चौधरी ने खुद की ही सरकार पर नाराजगी जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। हरीश चौधरी की नाराजगी की वजह है राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही विसंगति पर कोई विचार नहीं हुआ।

इतना ही नहीं इस बैठक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से किए गए विरोध की बातें भी सामने आई हैं, जिसे लेकर भी हरीश चौधरी ने नाराजगी जताई है।

हालांकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को लेकर उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह सही नहीं है और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है।

कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण में चल रही विसंगति को दूर करने को लेकर राजस्थान कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया।

जबकि पूरी उम्मीद थी कि मामला उठाया जाएगा। जब पूरी उम्मीदों के बाद भी ओबीसी आरक्षण की विसंगति को बुधवार रात हुई कैबिनेट मीटिंग में दुरुस्त नहीं किया गया और इस मामले को डेफर किया गया तो पूर्व मंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी मुखरित हो गए।

उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि कल कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया था, कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। हरीश चौधरी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि "मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं स्तब्ध हूं। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ूंगा।"

बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण में चल रही विसंगतियों को लेकर मामला बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट में उठा था,लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर अपनी बात रखते हुए इस पर और ज्यादा सोचने की बात कही। ऐसे में एक कैबिनेट के सदस्य की ओर से रखी बात के बाद प्रस्ताव को स्थगित किया गया। इस मामले को लेकर हुए विरोध में हरीश चौधरी ने ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऐसे में हरीश चौधरी ने सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य बिना नाम लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को निशाने पर लिया है।

कौन से मुद्दे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भविष्यवाणियाँ भी इस प्रकार की है। इंडिया टी.वी.-मैट्राइज़ ओपिनियन पोल्स के अनुसार, भाजपा को 46 प्रतिशत वोट तथा कांग्रेस को 42 प्रतिशत वोट मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये सर्वेक्षण अरविन्द केजरीवाल की "आप" की अच्छी सम्भावनाएं नहीं बता रहे हैं। सर्वेक्षण भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप को राज्य में 2 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिलेंगे। हाल ही के वर्षो में, भाजपा ने राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल हैं, में हर पाँच साल पर सरकार बदलने की "रिवॉल्विंग डोर" प्रवृत्ति को सफलतापूर्व चुनौती दी है। भाजपा रणनीतिकारों ने हिमाचल में प्रचार के दौरान महिला मतदाताओं तक पहुँचने पर जोर दिया है तथा भाजपा का सोच था कि महिला मतदाता हर पाँच साल पर सरकार को बदलने वाली प्रवत्ति को उलटने में भगवा पार्टी की मदद करेंगी। बुधवार को काँगड़ा तथा हमीरपुर में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुये, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देते हुये कहा था कि हिमाचल की महिलाओं ने तय कर लिया है कि वे हर पाँच साल बाद सरकार को बदलने के रिवाज को बदल देंगी। "इसलिये, अब इसे कोई चीज नहीं रोक सकती।"

प्रियंका की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का नेतृत्व किया है।

राष्ट्रीय मीडिया द्वारा सृजित वातावरण के विपरीत, इस पर्वतीय प्रदेश की चुनावी लड़ाई हर तरह से बहुत जबरदस्त रही है क्योंकि कांग्रेस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदा भाजपा सरकार को एक गम्भीर चुनौती देने में समर्थ रही है। प्रियंका गांधी ने स्थानीय मुद्दों को बखूबी उठाया और भाजपा को कड़ी चुनौती दी।

यह पहला अवसर था, जब पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी दोनों में से किसी ने भी हिमाचल में प्रचार नहीं किया। तथा प्रचार का सारा दायित्व को प्रियंका ने ही सँभाला। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनका गत वर्ष निधन हो गया था, की कमी जमीनी स्तर पर महसूस हुई क्योंकि राज्य में ऐसा कोई कांग्रेस नेता नहीं है, जिसका असर पूरे राज्य में हो।

चूँकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के कई दावेदार हैं, इसलिये पार्टी के विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी गुटों को सँभालने की जिम्मेदारी इस युवा पार्टी महासचिव के कन्धों पर ही थी। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने परस्पर विरोधी गुटों को बखूबी सँभाला है। अगर हिमाचल की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस की जीत हो जाती है तो प्रियंका पार्टी के एक उज्जवल सितारे के रूप में चमकेंगी तथा अगर भाजपा मतदाताओं की सत्ता-विरोधी प्रवृत्ति को पछाड़ कर, सत्ता में वापस आती है तथा प्रियंका के राजनैतिक भविष्य पर एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा।

गुजरात में भाजपा ने 38 मौजूदा मंत्रियों एवं विधायकों के टिकट काटे

भाजपा ने अभी 182 में से 160 उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है। पार्टी ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया है

- **भाजपा ने मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा सोलंकी को जामनगर सीट से मैदान में उतारा है।**

अहमदाबाद, 10 नवम्बर। गुजरात भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने कहा कि पार्टी ने अपने तीन दर्जन से अधिक मौजूदा विधायकों और कई दिग्गज नेताओं को आगामी चुनावी मुकाबले से बाहर करने के साथ अपनी गुजरात इकाई में एक पीढीगत बदलाव की शुरुआत की है।

भाजपा ने गुरुवार को कुल 182 उम्मीदवारों में से 160 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में लगातार सातवें कार्यकाल पर नजर रखते हुए, पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों को गिरा दिया, जिनमें से कुछ ने स्वेच्छा से घोषणा की कि वे 1 और 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आये हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया है तथा मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा सोलंकी को भी जामनगर से मैदान में उतारा है।

गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने बताया कि, अड़तीस विधायकों को बदल दिया गया है। भाजपा आमतौर पर अपने 20 प्रतिशत विधायकों को बदल देती है। चुनावी लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक है, अन्यथा यह गतिरोध को जन्म देगा। हमने कई युवाओं को टिकट दिया है। यह सूची एक पीढ़ीगत बदलाव दिखाती है।

पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा, प्रदीप सिंह जडेजा और कुछ अन्य सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी लड़ाई से खुद को वापस ले लिया है। यह पूछे जाने पर कि ये वरिष्ठ नेता चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इस पर पाटिल ने कहा, "उन्होंने स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इन सभी ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए अब वे संगठन के लिए काम करना चाहते हैं।

पार्टी ने आज जारी प्रत्याशियों की पहली सूची में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे युवा नेता हार्दिक पटेल को वीरमगाम सीट से उतारा है।

राहुल गांधी का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन संसद भवन में इसी तरह से माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। हम यह जानने की कोशिश में ही लगे रहते हैं कि क्या हुआ।"

उन्होंने आरोप लगाया, "चीन की सेना अन्दर घुस आई है, उसने 2000 वर्ग किलोमीटर (जमीन) पर कब्जा कर लिया है-माइक ऑफ।"

उन्होंने एक वीडियो, जिसे पार्टी के सोशल मीडिया विभाग ने ट्वीट किया है, मे कहा, "कोई मतलब नही कि हम क्या कह रहे हैं, उसे कोई नहीं सुन पायेगा, देखिये-माइक ऑफ।"

उन्होंने कहा कि कन्या कुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा बहुत जरूरी हो गई थी क्योंकि मुख्यधारा का अधिकांश मीडिया कांग्रेस की पहलों को कवर ही नहीं करता।

जब भीड़ ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसी ई.डी. के कथित दुरूपयोग का उल्लेख किया, तो उन्होंने कहा, "हम इसी ई.डी. शी-डी से डरने वाले नहीं है।"

दो दिन पहले, 2016 में ज्यादा मूल्य वाले नोटों की नोटबन्दी की छठी वर्षगाँठ पर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऐसा (नोटबंदी) करके "एक आर्थिक सुनामी खुली छोड़ दी थी।

बुधवार रात को नांदेड़ में हुई एक मीटिंग में, गांधी ने कहा कि टाटा-एयरबस मिलिट्री एयरक्राफ्ट वेन्चर तथा वेदान्ता-फॉक्सकॉन सेमीकन्डक्टर प्लान्ट जैसे प्रोजेक्ट महाराष्ट से हटाकर, गुजरात को दे दिये गये क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं।"

ये प्रोजेक्ट उन दो-तीन उद्योगपतियों को दे दिये जायेंगे, जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं तथा देश का पैसा उनके हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। बन्दरगाह, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, कृषि क्षेत्र इन लोगों को दिये जा चुके हैं।

पाली के पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के कई नोटिस देने के बाद भी धन जमा नहीं करवाया गया। कोर्ट की स्टे कॉपी देख ट्रांसपोर्ट नगर थाना विक्रम सिंह सांदू अपनी टीम के साथ वापस लौट गए, लेकिन बैंक की टीम दो घंटे तक वहीं रही। बैंक के वकील का दावा है कि दो कमरे सीज कर दिए गए हैं। मकान पर बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, लीगल मैनेजर, जोनल मैनजर व बैंक स्टाफ समेत पूरी टीम पुलिस जाब्ता के साथ पहुंची थी।

बैंक की टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे उदयपुर के एडवोकेट हनुमंत सिंह ने बताया कि बैंक ने सुरक्षा के लिए 2 गार्ड बैठा दिए हैं। उन्होंने बताया कि सीआई ने आंकलन रिपोर्ट फिर से करने का हवाला देकर सीज की कार्रवाई रुकवा दी।

थाना प्रभारी बोले कि इससे पहले 2019 में भी बैंक टीम मकान सीज करने पहुंची थी। उस समय पाली जिला मजिस्ट्रेट ने स्टे दिया था, जिस समय कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। इस मामले में सीआई विक्रम सिंह सांदू का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट ने स्टे दे रखा है।

दुष्कर्मी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में पीड़िता ने 11 जुलाई 2020 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और अभियुक्त पर 19 अक्टूबर 2019 से 11 जुलाई 2020 तक दुष्कर्म करने और डरा धमका कर डेढ़ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया था।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने जिरह में कहा कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे।

लेकिन अदालत ने पीड़िता के नाबालिग होने के चलते सहमति से बने संबंधों को भी दुष्कर्म की श्रेणी में माना और अभियुक्त को सजा सुनाई।

भारतीय मूल के अमरीकी नागरिकों को उत्साहवर्धक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का भी निर्धारण करेंगे जो फिलहाल वाइट हाउस में सत्तारूढ़ है। डैमोक्रेट सरकार की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की एक सीमा से अधिक वोट बटोरने की क्षमता के कारण डेमोक्रेट्स बहुमत में हैं। हैरिस देश की उपराष्ट्रपति होने के नाते सीनेट की प्रैसिडैन्ट भी हैं। ये चुनाव परिणाम वर्ष 2014 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों की जमीन तैयार करेंगे और डॉनल्ड ट्रम्प के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव दोबारा लड़ने में कठिनाईयां पैदा करेंगे।

अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 40 लाख लोग हैं। भारतीय लोग अमेरिका में अन्य देशों के प्रवासियों की तुलना में सबसे अधिक धन कमाने वाले लोग हैं। उनकी औसत आय एक लाख डॉलर है, जो देश की औसत आय से लगभग दोगुनी है।

यद्यपि यहां भारतीय की आबादी अमेरिका की कुल जनसंख्या की तुलना में करीब 1 प्रतिशत ही है, लेकिन इण्डियन -अमेरिकन्स बड़े राजनीतिक डोनर्स माने जाते हैं। इन्होंने ट्रम्प के पुनः चुनाव लड़ने की मुहिम पर 1 मिलियन डॉलर्स का योगदान दिया और डैमोक्रेट्स में पार्टी अध्यक्ष का नामांकन भरने वाले कई लोगों के लिए कुल 2 मिलियन डॉलर दिए।

पी.टी.आई. की एक न्यूज़ के अनुसार इलिनॉय की आठवीं कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट में 49 वर्षीय राजा कृष्णमूर्ति जीत के अच्छे अन्तर के साथ लगातार चौथी बार पुनः निर्वाचित हुए। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के अपने विरोधी उम्मीदवार क्रिस डार्गिस को पराजित किया। सिलीकॉन वैली में कैलीफोर्निया की 17वीं कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट में 46 वर्षीय इण्डियन-अमेरिकन रो खन्ना से रिपब्लिकन उम्मीदवार रितेश टण्डन को हराया।

चेन्नई में जन्मी एवं हाउस ऑफ रीप्रैजेन्टेटिव्ज़ की एक मात्र महिला सीनेटर प्रमिला जयपाल ने अपने रिपब्लिकन विरोधी क्लिफ मून को वॉशिंगन स्टेट की 7वीं कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट में हराया। सत्तावन वर्षीय बेड़ा कांग्रेस में सबसे लम्बे समय तक रहने वाले इण्डियन-अमेरिकन हैं। वह वर्ष 2013 से ही कैलीफोर्निया की 7वीं कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बेड़ा ने रिपब्लिकन प्रत्याशी टमिका हैमिल्टन को हराया है। कृष्णमूर्ति, खन्ना, जयपाल और बेड़ा देश की पूर्व संसद में भी सदस्य थे। जो भारतीय अमेरिकन देश की विभिन्न राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित हुए हैं, उनमें पैनसिल्वेनिया में अरविन्द वेंकट और तारिक खान, टैक्सास में सलमान भोजानी और सुलेमान लालानी, मिशिगन में सैन सिंह और रंजीव पुरी, इलिथॉय में नबीला सैयद, मेगन श्रीनिवास और केविन ओलिकल, जॉर्जिया में नब्लिया इस्लाम और फ़ारूख मुगल, मैरीलैण्ड में कुमार भर्वे और ओहायो में अनिता समानी। के.पी. जॉर्ज टैक्सास कोर्ट बैंड काउन्टी जज के पद पर, मोनिया सिंह टैक्सस हैरिस काउन्टी जज और अजय रमन ऑकलैण्ड काउन्टी कमिश्नर के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं।

इण्डियन-अमेरिकन उम्मीदवार कई ऐसे कड़े चुनावी मुकाबलों में फंसे, जिनमें से कईयों की जीत हो सकती है।

इनमें हैं- मिशिगन स्टेट सीनेट के लिए पद्मा कप्पा, न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट के लिए जेरेमी कूनी, पैन्सिल्वेनिया स्टेट हाउस के लिए अन्ना थॉमस, फोर्ट बैंड काउन्टी जज के लिए जूली मैथ्यू, फोर्ट बैंड काउन्टी जज के लिए सुरेन्द्रन पत्तला और इस बार टैक्सस सिटी काउन्सिल के लिए खड़े हुए ज़ोहेब क़ादरी। चुनावी दौड़ में अन्य इण्डियन अमेरिकन्स भी हैं- जैसे एरिज़ोना स्टेट सीनेट के लिए प्रिया सुन्दरेशन, ऑकलैण्ड सिटी काउन्सिल के लिए जनानी रामचन्द्रन, सॉल्ट लेक काउन्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए सिम गिल और वॉशिंगटन स्टेट सीनेट के लिए मानका धींगड़ा।

क्या राजस्थान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनका सर्वनाश हो रहा है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है तथा वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे पर कटाक्ष एवं प्रहार कर रहे हैं।

खाचरियावास और महेश जोशी एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर चला रहे हैं। स्थिति के और भी खराब होने की सम्भावना है क्योंकि गहलोत कमजोर होते जा रहे हैं तथा अपनी सरकार को एकजुट बनाये रखने में असमर्थ हो गये हैं तथा वे खासतौर से, अपने अस्तित्व को सुनिश्चित रखने पर फोकस कर रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908